

दैनिक जागरण

जीवन निरंतर चलने वाली एक यात्रा ही है

सुप्रीम कोर्ट की जांच समिति

नीट-यूजी प्रश्न पत्र लोके होने के मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेश प्रधान के त्यागपत्र की मांग को लेकर काकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो पांच सदस्यीय समिति गठित की गई, उसके बारे में यह स्पष्ट नहीं कि वह अपनी रिपोर्ट कब देगी। अच्छा होता कि इस समिति के लिए कोई समयसीमा तय की जाती। निरिदेह इस मामले में किसी निष्पक्ष जांच समिति की आवश्यकता थी। इस आवश्यकता की ही पूर्ति सुप्रीम कोर्ट ने की। अब अच्छा वह होगा कि सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों और सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों से लेस वह समिति अपनी रिपोर्ट यथाशीघ्र दे, ताकि उन कारणों को लेकर आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला समाप्त हो सके, जिनके चलते संसद मार्च में हिंसा हुई। इन प्रश्नों के स्पष्ट उत्तर सामने आना आवश्यक है कि क्या सोजेग समितियों की भीड़ में हिंसा पर आमादा तत्व भी शामिल थे या फिर पुलिस ने अकारण आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग किया? इन सवालों के जवाब तलाशते हुए सुप्रीम कोर्ट समिति यह भी स्पष्ट करे तो बेहतर कि क्या पुलिस को बिना अनुमति मिलते जा रहे सोजेग के संसद मार्च को संसद प्रवेश करने देना चाहिए था-और वह भी तब संसद का सत्र चल रहा था?

यदि कहीं कोई भीड़ संसद या विधानसभा की ओर कूच कर रही हो तो पुलिस का यह जिम्मेवारी बनती है कि वह उसे रोकें। हालां में झारखंड में नहीं किया गया। किसी भीड़ को संसद या विधानसभा की ओर जाने से रोकने के लिए पुलिस कितना बल प्रयोग करे, इसे किसी समिति के लिए तय कर पाना कठिन है, भले ही वह कितनी ही उच्चधिकार प्राप्त हो। तब तो मौके पर मौजूद पुलिस ही भीड़ के रुक-रुकने के आधार पर तय कर सकती है। ऐसे में उचित नहीं होगा कि वह समिति परना-प्रदर्शन का प्रोटोकाल तय करे, जिसकी आवश्यकता का उल्लेख सुप्रीम कोर्ट ने किया था। इसकी अनदेखी न की जाए कि सुप्रीम कोर्ट समिति केवल सोजेग और विपक्षी दलों के आरोपों की ही जांच नहीं करेगी। वह पुलिस पर हमला करने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोपों की भी जांच करेगी। ऐसा किया जाना इसलिए आवश्यक है, क्योंकि सोजेग के साथ विपक्षी दलों ने एक ऐसा मोहल बनाया, मानो भीड़ ने कुछ नहीं किया, वह बिल्कुल शांत एवं संतुलित थी और फिर भी पुलिस ने उस पर आंसू गैस के गोले दागे, लाठियों चलाई और पैलेट गन का इस्तेमाल किया। ऐसा नहीं था, वह इससे सिद्ध होता है कि संसद मार्च के दौरान उन्हा पुलिस के बल प्रयोग से कई प्रदर्शनकारी चोटिल हुए, वहीं अनेक पुलिसमैन भी घायल हुए, क्योंकि भीड़ ने बैरिकेडिंग तोड़कर उन पर पथराव किया था।

परती भूमि में कमी

उत्तराखंड में परती भूमि का दायरा घटना खेती-किसानी और खासकर पहाड़ की आर्थिकी के लिए सुखद संकेत है। सता जिलों में 15,286 हेक्टेयर परती भूमि काम होना बताता है कि लोगों ने दोबारा खेती की ओर रुख किया है। यह बदलाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लंबे समय से छोटी-बिछरी जमीन, सिंचाई का अभाव, वन्यजीवों से फसल हानि, मौसम की मार और पलायन जैसे कारकों से लोग खेती से विमुख हो रहे हैं। परिणामस्वरूप, खेती योग्य भूमि का बड़ा हिस्सा परती में बदलता गया। परती यानी ऐसी कृषि भूमि, जिस पर पहले खेती नहीं होती है और बाद में उसे छोड़ दिया गया। इसका घटना ग्रामीण अर्थव्यवस्था में संचालित बदलाव का संकेत है। यह लोग खेती को मजदूत परंपरागत गतिविधि के बजाय व्यावसायिक दृष्टि से अपनाने हैं तो इससे गांवों में रोजगार और आय के अवसर बढ़ेंगे तथा पहाड़ की आर्थिकी को भी मजबूती मिलेगी। हालांकि, तस्वीर का दूसरा पहलू भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वह जिलों में 7,389 हेक्टेयर परती भूमि बढ़ी है। इसलिए सरकार को इस सकारात्मक रुझान को स्थायी बनाने के लिए अधिक गंभीरता से प्रयास करेगा। इससे भी महत्वपूर्ण है उत्पादों के विपणन की ठोस व्यवस्था। किसान को यदि उसके उत्पाद का उचित मूल्य और बाजार की गरंटी मिले तो खेती आकर्षक बनेगी। परती भूमि में आई कमी को एक अवसर की तरह देखा जाना चाहिए। सरकार की नीतियां खेत से बाजार तक किसानों का साथ दें तो यह शुरुआत पहाड़ में खेती की मजबूत वापसी का आधार बन सकती है।

खेती को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी स्तर पर बुनियादी प्रयास और गंभीरता से होने चाहिए

बुजुर्ग बोझ नहीं, अनुभव की पूंजी

देवेंद्राज सुभार

देश में 2011 की जनगणना के अनुसार 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की संख्या लगभग 10 करोड़ थी और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुमान के मुताबिक 2050 तक यह आंकड़ा 30 करोड़ के पार पहुंच जाएगा। यही आने वाले तीन दशकों में भारत का एक पारंपरिक व्यक्ति बरिष्ठ नागरिक होगा। यह केवल एक सांख्यिकीय सूचना नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि हम अपने बुजुर्गों के साथ जिस उपेक्षापूर्ण से पेश आ रहे हैं, वह काल हमारी अपनी बुद्धि पर एक अवसर की घंटी बजाने लगे हैं।

सरकार ने 2007 में माता-पिता व बरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम बनाया था, जिसके तहत संतान अपने बुजुर्ग माता-पिता का भरण पोषण करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। इस कानून में वह प्रतिबंध भी है कि यदि कोई संतान अपने माता-पिता को संतुष्टि हस्तान्तरित करने के बाद उनको उपेक्षा करती है, तो वह हस्तान्तरण दर दिया जा सकता है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है

बुजुर्गों के प्रति समीचीन लोको को अग्रणी जिम्मेवारी को समझना होगा, तभी सही से उनकी देखभाल संभव है

कि इस कानून की जानकारी अधिकांश बुजुर्गों को ही नहीं, और जिन्हें है भी, वे अपनी संतान के विरुद्ध अजलाज जाने से हिलकने हैं। सामाजिक न्याय मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि इस कानून के तहत दर्ज मामलों में से आधे से अधिक शिकायतें संतुष्टि विवाद से जुड़ी होती हैं, न कि भावनात्मक उपेक्षा से।

एक पारदर्शक जिस पर बहुत कम चर्चा होती है, वह है वृद्ध महिलाओं की स्थिति। विधवा या अकेली बुजुर्ग महिलाएं आर्थिक रूप से सबसे अधिक असुरक्षित हैं, क्योंकि परिवारिक रूप से संतुष्टि और पेंशन पर उनका सीधा अधिकार संश्लेषित नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो स्थिति और विचित्र है, जहां विधवा पेंशन योजना की राशि इतनी कम है कि वह जीवनव्यापन के लिए पर्याप्त नहीं। शहरी



राजकुमार सिंह

अजर सांसद संसदीय कार्यवाही की आपनी प्राथमिक संवैधानिक जिम्मेवारी का निर्वाह ही नहीं कर रहे तो आखिर और क्या ही करते होंगे?

प्रति मिनट की कार्यवाही पर करीब ढाई लाख रुपये के खर्च की बर्बादी के पुराने आंकड़े देहतरात हुए संसद की गिरती उत्पादकता पर फिर चिंता जताई जा रही है। मानसून सत्र में मात्र 19 प्रतिशत कामकाज ही हो पया और 173 कार्य घंटे बर्बाद हो गए। दो महत्वपूर्ण विधेयक मात्र 14 मिनट की चर्चा में परित कर दिए गए हैं। विना किसी चर्चा के जाहिर है कि संसद में काम कम हुआ और हंगामा ज्यादा उठे। उसके लिए कोई जिम्मेदार भी तलाश नहीं चाहिए। हमारी संसदीय राजनीति में हंगामे के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराने की परंपरा रही है। बेकार हंगामे की शुरुआत अक्सर विपक्ष की ओर से ही होती है, मगर अकारण तो कुछ भी नहीं होता। किसी भी समस्या का समाधान उसके कारणों के निवारण की मांग करता है, लेकिन हम कारणों से ही मुंह चुरा लेने के अभ्यस्त हो चुके हैं। विपक्ष और सत्तापक्ष को भूमिकाएं बदलें ही भूत-भूमि-एवं बदल जाना गैर-जिम्मेदार और अवसरवादी राजनीति ज्यादा है।

2014 से पहले नेता-प्रतिपक्ष चुनना स्वरज और अरुण जेटेली संसद सभा सत्तापक्ष की जिम्मेदारी तब संसदीय गतिरोध को भी संसदीय राजनीति का संवैधानिक उपकरण बताते थे, पर सत्ता

पाने के बाद भाजपा का सोच बदल गया। तब संसदीय गतिरोध के लिए भाजपा को कठपंते में खड़ा करने वाली कांग्रेस अब अपनी वैसी ही भूमिका संसदा लोकतांत्रिक उठारा रही है। संसदीय गतिरोध और उसके जरिये सड़क की राजनीति का एजेंडा तब करने की प्रवृत्ति नहीं है, लेकिन उसका लगातार बढ़ते जाना खतरनाक है। पहले जो विरोध वैचारिक या मुदा आधारित होता था, अब वह दलगत रंजित में बदल गया लगता है। कि एक-दूसरे का परिणाम और प्रभाव है कि एक-दूसरे पर टिप्पणों करते हुए भाषाई मयावी या तार-तार की जा रही है।

संसद के मानसून सत्र जैसा हंगामा पहली बार नहीं हुआ। नरसिंह सिंह के प्रभारनयित्वकाल में हर्ष महता कांड पर भी संसद में ऐसे ही दृश्य देखे गए थे। मनमोहन सिंह के समय टू-जी सेक्युडर और कोयला घोटाले पर संसद कई दिनों तक उप रही थी। तब कांग्रेस सत्ता में थी और भाजपा विपक्ष में। वह राष्ट्र हित था और वह राष्ट्र विरोध। इस अतार्किक सोच दलों-नेताओं का हो सकता है, जतना का नहीं है। इस बात हमारे का संकेत सत्र की शुरुआत के साथ ही मिन गया था। नीट-यूजी परर लोक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेश प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर काकरोच

एकाकी होता जीवन का संध्या काल

यह समाचार सामाजिक चेतना को हकझोरे वाला था कि सोवियत, हरियाणा के बुद्धाश्रम में रह रहे एक खेवबुद्ध ने की मूल्य के बाद उनकी तीनों बेटियों या नाती-नातियों में से कोई भी उसके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ। बेटियों ने वीडियो काल पर अंतिम संस्कार करना चुना। विद्वान पति प्रतिष्ठित व्यापारी थे। उन्होंने अपनी तीनों बेटियों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया और उनका विवाह कर पिला होता का दायित्व निभाई किया। सभी बेटियां न तो उनके अंतिम संस्कार में आई और न ही तेहवहीं में। पिछले कुछ वर्षों में वृद्ध माता-पिता अपनी संतानों द्वारा अणुप्राणित, उपेक्षित और तिरस्कृत हुए। बुजुर्ग भरा-पूर परिवार और संसाधन होने के बाद अपने मकानों या बुद्धाश्रमों में एकाकी जीवन जीने को अभिप्राय हैं। वह स्वार्थी, यौक्तिक और संवेदनहीन होते जा रहे समाज के रगेबोटीकरण का प्रतीक हैं।



प्रो. रमेश सिंह

तीन बेटियों के अंतिम संस्कार में शामिल न होने को केवल अमानवीय कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके पीछे कुछ ठोस सामाजिक और आर्थिक कारण काम कर रहे हैं। पहला है-समय की पुनर्निर्भाषा। आज के शहरी जीवन में समय को उत्पादकता से जोड़ दिया गया है। हर गतिविधि का मूल्यकाल इस अर्थकाल पर होता है कि, उससे करियर या आय में कितनी वृद्धि होगी। अंतिम संस्कार इस पैमाने पर खरा नहीं उठता। उससे कोई स्वायत्तसिद्धि या लाभ नहीं होता। इसलिए वह महत्वहीन हो जाता है। दूसरा कारण है भवभावक दूरी। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक माता-पिता से नहीं मिलता तो उनके प्रति लगाव कम हो जाता है। मूल्य की जानकारी एक निजी सूचना बनकर रह जाती है, एक अज्ञात नहीं। तीसरा कारण है सामाजिक र्व्यवस्था में बदलाव। पहले यदि कोई संतान माता-पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होती थी तो उसे अपराध-बोध और एक क्रिम के सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता था। आज ऐसे व्यवहार को 'व्यस्त जीवन जनित विवर्तना' कहकर सामाजिकृत सा कर दिया गया है। परंपरागत रूप

से भारतीय समाज में बेटियों से यह उम्मेद की जाती है कि वे माता-पिता की अधिक देखभाल करेंगी, पर अब बेटियों की नौकर की कारण उसी प्रतिस्पर्धी व्यवस्था का हिस्सा बन जा रही हैं। जिसमें पुरुष पक्ष से थे। उनका व्यवहार भी बेटी जैसा होता जा रहा है। इसका अर्थ यह नहीं कि बेटियां संवेदनहीन हो गई हैं, बल्कि यह है कि बाजार आधारित आर्थिकी ने स्त्री और पुरुष को 45-45- उपभोक्ता में अव्यक्तित्व कर दिया है। पिछले कुछ दशकों में संयुक्त परिवार टूटे हैं और एकल परिवार का चलन बढ़ा है। शहरीकरण, शिक्षा और रोजगार के अवसरों के कारण लोगों का पलायन/विस्थापन हुआ है। भौगोलिक दूरी का सीधा असर बुजुर्ग माता-पिता पर पड़ा है। उनके पास तो विफल बच्चे हैं-या तो अकेले रहे या बुद्धाश्रम में। दोनों ही स्थितियों में उनकी देखभाल और भवानात्मक जरूरतें पूरी नहीं हो पाईं। अभाव स्वतंत्रता, निजता की चाह और असौम्य मौतिका ने भी परिवारों को नींव को हिलाया है।

जब पति-पत्नी दोनों नौकर की करते हैं, तो बुद्धाश्रम को एक व्यावहारिक समाधान मानकर बुजुर्गों को निवासित कर दिया जाता है। प्रारंभ में मोहते में मिलने का वादा होता है। फिर वह अविश्व बहती जाती है। फोन पर बात भी औपचारिक होती जाती है। धीरे-धीरे बुजुर्ग बच्चों के जीवन से निष्कासित हो जाते हैं।

राष्ट्रीय वृद्धजन आयोग और कुछ स्वतंत्र संस्थाओं के सर्वेक्षण बताते हैं कि भारत में 15 प्रतिशत से अधिक वरिष्ठ नगरपाल अकेले रहते हैं। महानगरों में वह प्रतिशत 25 के आसपास है। बुद्धाश्रमों में रहने वाले 60 प्रतिशत से अधिक लोगों के बच्चे देश के भीतर ही रहते हैं। बुद्धाश्रमों में प्रवेश लेने वाले 40 प्रतिशत बुजुर्गों का मूल कारण आर्थिक तंगी से ज्यादा आत्मकेतित एवं उपयोगितावादी मूल्यचेतना और पथचाल व्यवहार जीवनशैली है। आज अंतिम संस्कार के लिए 'संस्कृत जंगल' जैसी सेवा बहुत कंपनियां ऑनलाइन आ चुकी हैं। परिवार सामक संस्था परतवीर समाज की सबसे बड़ी विशेषता रही है। उसे बचाने और मजबूत करती हैं कि वे माता-पिता की अधिक देखभाल करेंगी, पर अब बेटियों की नौकर की कारण उसी प्रतिस्पर्धी व्यवस्था का हिस्सा बन जा रही हैं। जिसमें पुरुष पक्ष से थे। उनका व्यवहार भी बेटी जैसा होता जा रहा है। इसका अर्थ यह नहीं कि बेटियां संवेदनहीन हो गई हैं, बल्कि यह है कि बाजार आधारित आर्थिकी ने स्त्री और पुरुष को 45-45- उपभोक्ता में अव्यक्तित्व कर दिया है। पिछले कुछ दशकों में संयुक्त परिवार टूटे हैं और एकल परिवार का चलन बढ़ा है। शहरीकरण, शिक्षा और रोजगार के अवसरों के कारण लोगों का पलायन/विस्थापन हुआ है। भौगोलिक दूरी का सीधा असर बुजुर्ग माता-पिता पर पड़ा है। उनके पास तो विफल बच्चे हैं-या तो अकेले रहे या बुद्धाश्रम में। दोनों ही स्थितियों में उनकी देखभाल और भवानात्मक जरूरतें पूरी नहीं हो पाईं। अभाव स्वतंत्रता, निजता की चाह और असौम्य मौतिका ने भी परिवारों को नींव को हिलाया है।

मेलावतस

गुरुवार को 'सुधार घटती गुणवत्ता

गुरुवार को 'सुधार घटती गुणवत्ता' शीर्षक से प्रकाशित लेख देश के राजमार्गों की वर्तमान स्थिति पर गंभीर और विचारणीय प्रश्न खड़े करता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश में राष्ट्रीय राजमार्गों का जाल तेजी से बिखर रहा है, लेकिन इसके साथ ही सड़कों की गुणवत्ता में कमी, बढ़ती टुकटुक-और प्रशासनिक स्तर पर भ्रष्टाचार की झलक भी सामने दिखाई देती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर सड़कों की गुणवत्ता में गिरावट का कारण बता रहा है, जब इससे व्यवस्था में घातल पर सुधार दिखाई दे। मंत्री के रूप में उनका कार्यालय एक दायरे से अधिक का हो चुका है। इनमें लंबे समय के बाद भी यदि स्वयं मंत्री को वह स्थिति करना पड़े कि राष्ट्रीय राजमार्गों प्राधिकरण में अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से तकनीकी व वित्तीय खोटापे तय हो रहे हैं, तो यह सोचें तभी पर प्रशासनिक निरीक्षण पर सख्त खड़े करत है। लोक न केवल सड़क हादसों में अपनी जान गंवा रहे हैं, बल्कि उनके द्वारा ईमानदारी से चुकाया गए पैसा भी भ्रष्टाचार की घंटे चढ़ रहा है। उनका मानना ​​का विकास केवल आंकड़ों में नहीं, बल्कि जनता की सुरक्षा और टिकाऊ निर्माण में दिखना चाहिए। तभी सही मायने में सुधार संभव होगा।

पौर तोमर, किकनगंज, दिल्ली

विवरास लगभग खो चुके हैं। सत्रावसान के बाद उनकी चाय पार्टी का भी विषय ने बहिष्कार किया। जाहिर है, यह सब संसदीय लोकतंत्र की सुखद तस्वीर पेश नहीं करता, लेकिन क्या आपको किसी के चेहरे पर शिकन भी नजर आती है? नहीं, क्योंकि संसद चलने न चलने से न सत्तापक्ष को फर्क पड़ता है और न ही विपक्ष को। बिना बहस और जवाबतलबी के विधेयक पारित हो जाएं तो सत्तापक्ष के लिए इससे बेहतर स्थिति क्या हो सकती है? दोनों ही सदनों में विपक्ष को भी संसद से बाहर सड़क और चुनाव की राजनीति के लिए अपने मुर्खों को धार देने का मौका मिल रहा है। दोनों ही एक-दूसरे को असौकरात्मक बता रहे हैं, पर कौन कितना लोकतांत्रिक है, वह जतना बखूबी जानती है।

संसदीय गतिरोध भी समाधान का रास्ता निकालने को कवायद सदन के समापित और संसदीय कार्य मंत्री कर सकते हैं, लेकिन विवेकना यह है कि इन दोनों के भी विपक्ष से संबंध सहज नहीं। राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्वकाल में शुरू हुई संसद में 'इल्ला गिरो' की खतरनाक परंपरा तोड़ने की जरूरत किसी ने भी नहीं महसूस की। आज भी सदन में दोनों ही और हंगामावर्ती की कमी नहीं, लेकिन यदि संसदीय कार्य मंत्री भी उसी गिरोड का सदस्य बनते दिखें तो विपक्ष से संवाद की पहल नहीं करेगा? पिछली लोकसभा में विपक्षी सांसदों के इकाई निर्वाचन के बाद से स्पौर ओम बिरला भी विपक्ष का

(लेखक वरिष्ठ फकार एवं राष्ट्रीय विश्लेषक) response@jagran.com



चिंत का संतुलन

हमारे प्राचीन ग्रंथ अनुकरणयोग ज्ञान से समृद्ध हैं। इसी संदर्भ में उपनिषदों में उल्लेख है कि ब्रह्म तत्व की प्राप्ति न तो बलवर्तन द्वारा संभव है और न ही सदा प्रदाम में रहते वही अनुशासनहीन व्यक्ति प्राप्त। जो विवेकी व्यक्ति संतुलन और एकता के साथ उस परम सत्ता की खोज करता है, केवल वही उससे एकाकार स्थापित कर पाता है। इस स्थूल जगत और हमारी चेतना के बीच संपर्क और तारतम्य का सूत्र मर्म के माध्यम से ही साधना होता है। जातिधर्मों द्वारा जगत का अनुभव लेकर कर्माधर्मों द्वारा व्यवहार करने का क्रम निबंध रूप से केवल मर्म से ही संभव है। हमें चेतना का अनुभव भी मर्म के माध्यम से ही हो रहा है। ऐसे में मर्म का निरीक्षण में रहना, संतुलन में रहना आवश्यक है, क्योंकि मर्म का पीछड़ा होना या अतिवर्तिता होना ही मानव जीवन की चिंता का और दयनीय अवस्था का कारण है। यदि शरीर दुर्बल होता है मर्म अत्यंत दुर्बल, अवसादग्रस्त, अत्यंत क्रोधा और प्रेम का मर्म नहीं समझा और बिना प्रेम के समझे प्रत्येक तत्व से एकाकार एक कल्पना प्रगम हो जाती। जिस हृदय में प्रेम का अभाव होता है, वह जीवन की पूर्णता में समझने से वंचित रह जाएगा।

आज आवश्यक है सम्यक स्थापित करने की। उस मार्ग का निर्माण करने की, जो दुर्बल और अस्थिरता हो बिना पराधर्मा का मार्ग हीनता करता हो। इस सत्य में ही वास्तव में उद्धार संभव है, क्योंकि किसी तरह की अति अंततः सम्यक और एक कल्पना होती है। यही मार्ग है जो ग्रंथ और पुरुष के मध्य में मानवीय विकाश है। हमें न पंचवक्त्र होना है, न ही पशुपुत्र। हमें तो मानवीय गुणों की सर्वश्रेष्ठ संतुलना को प्राप्त करना है। इस उच्चायन अवस्था की स्थापना ही ब्रह्म तत्व का अनुभव है, जहां ज्ञान, ज्ञात और ज्ञेय एक हो जाते हैं।

आदित्य नारायण अवस्थी

निर्माण कार्य से जुड़ी जिम्मेदारी

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा अपने ही विभाग की कर्मियों और भ्रष्टाचार को स्वीकार करना निश्चय रूप से साहस का संकेत हो सकता है, लेकिन बहर वृत्त के लंबे काकिलाल के बाद यह स्वीकारणीयता अत्यंतभय से अधिक व्यवस्था की विलक्षण का प्रमाण बन जाती है। अन्य केवल ठेकेदारों को कारी सूची में डालने की चेतावनी मिल रही है, जिसमें घंटियां चलाया गया, जिसने उन्हें स्वीकृति दी और जिसने निगरानी में आंशिक मंद-तीनों की जवाबदेही ठोकी नहीं चाहिए। दोषी ठेकेदार के साथ संबंधित अधिकारी और सर्वश्रेष्ठ तभी को कटौत करें। देश को ऐसी व्यवस्था चाहिए, जिसमें सड़क बनने के बाद उसकी गुणवत्ता पर साक्ष्य प्राप्त की जाती है, न ही जगह, बल्कि निष्ठा के प्रत्येक चरण में पारदर्शिता व सर्वजनिक जवाबदेही सुनिश्चित हो।

मिर्मलेश कुमार सिंह चौहान, लखनऊ

इस संध में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अवकाश दीक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए फ़ैलाफ़ा यादर आमंत्रित है। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं। अपने पत्र इस पते पर भेजें: दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण, ई-210-211, सेक्टर-63, नोएडा ई-मेल: response@jagran.com



डा. संजय वामी
एसीस्टेंट प्रोफेसर,
केएट युनिवर्सिटी,
ग्रेटर नोएडा

चांद पर मानव बस्तियां बसाने के सपने को साकार करने के प्रयासों का फिलहाल अंजाम यह है कि ये बांध अभी नक्शों और योजनाओं में दर्ज हैं। पतंग उड़ान उद्देश्य के लिए अब चंद्रमा दुनिया में शुरू हुई नई स्पेस-रेस का पड़ाव फिर से बनने जा रहा है, यह लंबी अंतरिक्ष यात्राओं के लिए पड़ाव के रूप में उसके उपयोग से जुड़ा है। इस संघर्ष में यह नई सूचना काफी मायने रखती है कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन वासी इस्त्रो को अपने 'मन वेस' कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। इसका राजमहारा हल में वेगलु स्थित इस्त्रो मुख्यालय में हुई भारत-अमेरिका सांख्यिक स्पेस ज्वाइंट वरिगन ग्रुप की बैठक में हुआ है।

अंतरिक्ष विज्ञान, बाणिज्यिक अंतरिक्ष गतिविधियों और मानव अंतरिक्ष उड़ान तकनीक में सहयोग बढ़ाने के साथ वैज्ञानिक अंतरिक्षों के आदान-प्रदान को सहज करना और इस्त्रो के बीच साक्षात्-लेखन के बारे में यह नई सूचना जल्दी है, लेकिन इस्त्रो और उसके चंद्र-अधिन्याय (चंद्रमण) की प्रगति और यह मूल्य वाजह है, जो चंद्रमा के मामले में अमेरिका को भारत की ओर देखने के लिए प्रेरित कर रहा है। इस बदलते नजरे में भारत की भूमिका केवल एक ऐसे देश की नहीं है जिसने अपेक्षाकृत कम लागत में चंद्रमा पर यान उतार दिया। बल्कि भारत ने वैज्ञानिक विराट को चंद्रमा की ऐसी सुनवाई दी है, जिसके कारण आज उनका दक्षिणी ध्रुव दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण अंतरिक्ष क्षेत्रों में गिना जा रहा है।

हालांकि यहां एक तथ्यात्मक अंतर समझना जरूरी है। इसे सोधें-सोधें 'इस्त्रो-नासा का नया मूल्य वेस समझना' करना अभी जल्दबाजी होगी। नासा की ओर से इस्त्रो को मूल्य वेस कार्यक्रम में शामिल होकर के निमंत्रण का एक उल्लेखीय पहलू यह है कि दोनों मुलकों के बीच ऐसी साझेदारी की जगह पारस्परिक से मौजूद है। वर्ष 2023 में भारत की ओर से नासा के जिस आर्टिफिशियल एक्सप्लॉरर्स के सैटलाइट डॉच पर सहमति हुई है, यह उसकी अगली कड़ी है। फिर भी इस निमंत्रण का महत्व किसी औपचारिक संधि की भाषा से कहीं बढ़ा है। यह इसलिए कि मौजूदा वक्त में चंद्रमा पर केवल यान और इंसान को लेजाना उतारने की ही प्रतिक्रिया नहीं चल रही। बल्कि अब सवाल यह है कि

आजकल

चंद्रमा तक दौड़ के बीच नासा का न्योता

तमाम वैज्ञानिक और खगोलीय प्रगति के बावजूद मानवीय कदमों की छाप अभी तक पृथ्वी के इकलौते उपग्रह चंद्रमा के बाहर नहीं पड़ पाई है। इतना ही नहीं, 1972 तक चले छह अमेरिकी चंद्र-अभियानों के अलावा किसी अन्य देश का नागरिक चांद पर चहलकदमी का गौरव भी हासिल नहीं कर सका है। ये बाते जितनी खटकने वाली हैं, उतनी ही आश्चर्यस्तदाक भी हैं कि अंतरिक्ष अभी इंरसानी लालच के दर्तरी में आने से बचा हुआ है। ऐसे में नासा की ओर से भारत को साथ मिलकर काम करने का न्योता देना भारत की महता भी दर्शाता है

वहां लंबे समय तक कौन वैज्ञानिक उपस्थिति बना सकता है, कौन चंद्र-संसाधनों को बेहतर समझ सकता है, कौन वहां से आगे मंगल और अन्य गहरे अंतरिक्ष अभियानों के लिए रास्ता बना सकता है और कौन इस नई अंतरिक्ष व्यवस्था के नियमों तथा तकनीकों को आधार देने में भागीदार होगा। रूस से इस्त्रो की कहानी विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है।

पानी की खोज से आरंभ कहानी : उल्लेखनीय है कि भारत का पहला चंद्र अभियान चंद्रमन-1 साल 2008 में गया था। उस वक्त शाहद ही किसी ने यह उम्मीद की थी कि वह अपेक्षाकृत छोटा मिशन आने वाले वर्षों में चंद्रमा की वैश्विक खोज की दिशा प्रभावित करेगा। चंद्रमन-1 ने चंद्रमा की रासायनिक, खनिज और भू-आकृतियों की मीपिंग की। उसके 11 वैज्ञानिक उपकरणों में भारतीय और विश्वीय दोनों संस्थाओं ने योगदान शामिल था। इस मिशन का सबसे महत्वपूर्ण नतीजा चंद्र सतह पर हाइड्रोजन और पानी के अणुओं तथा स्थानीय छाया वाले ध्रुवीय क्षेत्रों में जल-बर्फ के संकेतों की पहचान करना था।

इस खोज का महत्व केवल इतना नहीं था कि इसने चंद्रमा पर पानी मौजूदगी के प्रमाण जुटाए। पानी की मौजूदगी का एक अर्थ जीवन की संभावना को आधार मिलना है। चूंकि पानी को आक्सीजन और हाइड्रोजन में विभाजित किया जा सकता है, इसलिए हाइड्रोजन-आक्सीजन रॉकेट ईंधन का आधार बन सकता है। इस तरह इस मानचौकी को दोस आधुनिक चिह्न चंद्रमा पर पानी भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए संश्लेषण बन सकता है।

प्रयोगशाला से आगे : यहाँ नासा का मूल बेस कार्यक्रम कहानी में प्रवेश करता है। इसी सिलसिले में भारत ने 21 जुन 2023 को आर्टेमिस एक्वाडर्स पर हस्ताक्षर किए थे। उस समय भारत ऐसा करने वाला 27वां देश था। इन एक्वाडर्स का उद्देश्य चंद्रमा और उससे आगे अंतरिक्ष अन्वेषण में शान्तिपूर्ण, पारदर्शी और जिम्मेदार सहयोग के लिए कुछ साझा सिद्धांत विकसित करना है। नमून वैज्ञानिक आंकड़ों को साबंजित करने और अंतरिक्ष संसाधनों के जिम्मेदार उपयोग जैसे विषय शामिल हैं। इसलिए, 2026 का मूल बेस निमंत्रण उस प्रक्रिया की अगली कड़ी है। अतः, नसा अब चंद्रमा पर दीर्घकालिक मानव उपस्थिति की दिशा में काम कर रहा है। उसके वर्तमान मूल बेस कार्यक्रम का उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के आसपास ऐसी स्थानीय उपग्रह संचरण विकसित करना है जो मनुष्यों को वहां रहने, काम करने और वैज्ञानिक अनुसंधान करने में सक्षम बनाए। नसा ने मई 2026 में मूल बेस के लिए रोजर और कार्गो लैंडर दंपती 'नई योजनाओं' की घोषणा की थी। वर्ष 2028 में वहां कुछ प्राथमिक प्रयोगशाला का लक्ष्य रहा है। इसलिए नसा-इस्त्रो के ताजा गठजोड़ की संभावना वाली खबर को केवल 'अमेरिका ने भारत को चांद पर बुलाया' की सरनसोखेज भाषा में पढ़ना पड़ना नहीं होगा। असली सवाल यह है कि अमेरिका ने भारत को न्योता क्यों भेजा है? इसका उत्तर भारत की पिछली चंद्र उद्यमिताओं में छिपा है।

लेकिन यहां सावधानी भी जरूरी है। अमेरिका के साथ बढ़ती साझेदारी का अर्थ यह नहीं होना चाहिए कि भारत



भारत चंद्रमा पर अपेक्षाकृत बहुत कम लागत में अपना यान उतार चुका है।

प्रतीकात्मक

चांद से जुड़ी तकनीकी और मनोवैज्ञानिक चुनौतियां

कभी चांद हमारे लिए आकाश में चमकता एक सुंदर गोला था। फिर वह अमेरिका और सोवियत संघ की अंतरिक्ष प्रतियोगी का लक्ष्य बना। आज वह पृथ्वी से बाहर मानव सभ्यता की अगली प्रयोगशाला बन रहा है। इस बदलाव में भारत का योगदान इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत ने चंद्रमा की उस कहानी को वैज्ञानिक आधार दिया जिसमें पानी, ध्रुवीय क्षेत्र और भविष्य के संसाधनों की चर्चा संभव हुई। चंद्रमा कार्यक्रम नसा ने यह भी दिखाया कि अंतरिक्ष अन्वेषण केवल असंभव बजट वाले देशों का विशेषाधिकार नहीं है। अगर नासा का निमंत्रण भारत के लिए नई जिम्मेदारी लेकर आया है। भारत को इस अवसर को केवल राष्ट्रीय गौरव के क्षण के रूप में नहीं, बल्कि अगले 25 वर्षों की वैज्ञानिक-तकनीकी रणनीति और ऐसी प्रौद्योगिकी आगामी के रूप में देखना होगा जो भारतीय विकास व स्वावलंबन की राह खोलता हो।

एक विकास और एक सफलता : भारत के चंद्र अभियानों की अगली कहानी थोड़ी जटिल रही। अपनी कई प्राथमिकताओं को किसी दूसरे देश के कार्यक्रम में विलीन कर देना, अंतरिक्ष सहयोग का सबसे अच्छा मॉडल है जिसमें साझेदार अपनी क्षमताएं साझा करें, लेकिन अपनी वैज्ञानिक स्वयंमता भी बनाए रखें। भारत को नासा से तकनीक और अनुभव

चंद्रयान-2 का विक्रम लैंडर सितंबर 2019 में दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में साफ लैंडिंग नहीं कर पाया। यह विफलता इस्त्रो के लिए तकनीकी और मनोवैज्ञानिक दोनों अर्थों में चुनौती थी। लेकिन अंतरिक्ष अनुसंधान की असली शक्ति शाहद इसी विंदु पर दिखाई देती है - असफलता को अंतिम निष्कर्ष नहीं, अपल प्रयोग की सामग्री बनाना। इस्त्रो का अगला चंद्र मिशन चंद्रयान-3 उसी अनुभव से निकला था। 14 जुलाई 2023 को प्रेषित यह मिशन 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में सफलतापूर्वक उतरा।

चंद्रमा के इस क्षेत्र में अपना यान सफलतापूर्वक उतरने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना और अमेरिका, रूस तथा चीन के बाद चांद पर साफ लैंडिंग करने वाला चौथा देश। यह उल्लेख केवल राष्ट्रीय गौरव का विषय नहीं था। असली उपलब्धि उस वैज्ञानिक प्रयोगशाला की थी जो चंद्रमा की सतह पर सक्रिय हुई। विक्रम लैंडर और प्रोडर रोवर ने चंद्र सतह की संरचना, तापीय गुणों, भूकंपीय गतिविधि और तत्वों संरचना के बारे

में प्रत्यक्ष आंकड़े जुटाए। चंद्रयान-3 के उपकरणों ने सल्फर, कैल्शियम, आयर्न, क्रोमियम, टाट्रेनियम, मैंगनीज, आक्सीजन और लिथियम जैसे तत्वों की मौजूदगी की पुष्टि की। लेकिन चंद्रयान-3 की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों को केवल 'हम चांद पर उतर गए' कहकर सीमित कर देना उसके वैज्ञानिक योगदान को छोटा करना होगा। मसलन, चंद्रयान-3 के एक अहम उपकरण ने चंद्रमा के दक्षिणी उच्च आक्षा वाला क्षेत्र में सतह के सबसे ऊपरी लगभग 10 सेंटीमीटर हिस्से के तापमान और तापीय गुणों का प्रत्यक्ष मापन किया। इस्त्रो के अनुसार इससे पहले ध्रुवीय क्षेत्र की ऐसी प्रत्यक्ष उपलब्धि तापीय जानकारी उपलब्ध नहीं थी। यह जानकारी भविष्य में चंद्रमा के संसाधनों के वयोग और वहां काम करने वाले उपकरणों तथा मानव अभियानों की डिजाइन के लिए उपयोगी हो सकती है। सभी चंद्रयान-3 ने चंद्रमा को केवल छुआ नहीं, बल्कि उसका सटीक मानचित्र बनाया।

(डा. संजय वामी)

पोर्ट

आजरा कुली की समस्या पर घानाकई के लिए मध्य प्रदेश में एक शिकारकर्ता ने सखीत अतिकारी के समक्ष कुले का मुजौटा पहा। इस मुद्दे पर जागरूकता प्रसार के लिए ऐसी ही नाटकीय प्रदर्शन की जरूरत है।

कार्तिक दिवदरम@KartiPC

बंदे मातरम् के पछड़े में छोड़े गुरी तरह फस गई है। अपनी फजीहत से बचने के लिए अब वह बंदे मातरम् के इतिहास में घुस गईं। यह नैरेटिव छाय है, क्योंकि सरस के मानसून सत्र से पछड़े बंदे मातरम् को कानूनी उज्जी प्राप्त नहीं है।

संजय निरुपम@sanjaynirupam

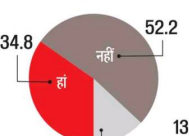
विरोध बंदे मातरम् का है या बंदे मातरम् पर कानून भी है बनाया, इसलिए विविध कानून हैं? विषय ने तब तक रह गया कि नरेन्द्र मोदी जो कहेंगे आंख मूंद कर उसका विरोध करना है। आशोक श्रीवास्तव@AshokShrivastava6

भारत में अमेरिकी राजदूत ने कुछ भी गलत नहीं कहा है। कश्मीर भारत में शामिल हुआ और उसका हिस्सा बन गया और विभाजन के बाद पाकिस्तान ने ही उस पर कब्जा करने की कोशिश की थी।

जागरण जनमत

कल का परिणाम

व्या डब्ल्यूटीसी फाइनल के लिए भारत की क्या आसाम होती दिख रही है?



नतीजा अभी घोषित नहीं है।

आज का सवाल

व्या डब्ल्यूटीसी फाइनल के लिए भारत की क्या आसाम होती दिख रही है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पढ़कों का मत है

जनपथ

बोटींग कर डल डील में खल जुल गया दिग्गम, तब बोटी कर्मचारी है भारत का ही भाग। भारत का ही भाग युवा युव दुनिया सारी को संरक्षित गौर वलकर बोटींग। ले भारत का पक्ष कीजिए खुलकर बोटींग, अमेरिकी टूरिस्ट करे तब तब में बोटींग!!

-आमि प्रवेशा विवारी



शशि शुकल
समादौष्य प्रभारी,
राजी

झा खंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) और झारखंड कर्मचारी सच आयोग (जेएसएससी) की परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं की जांच और अन्य मांगों को लेकर रांची के जयपाल सिंह स्टडीस में 26 दिनों तक चले छात्र आंदोलन की समाप्ति अच्छे फैसलों के साथ हुई है। जंतर-मंतर के बाद छात्रों का सबसे बड़ा आंदोलन के रूप में खूबियां या चुके रांची के छात्र आंदोलन ने छात्र छात्रों और युवाओं की ताकत का अहसास कराया, वहीं इस मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी अच्छा निर्णय लेने के लिए बाध्य रहे।

जेपीएससी और जेएसएससी की नियुक्ति परीक्षाओं के सिस्टम में व्यापक बदलाव करने की प्रक्रिया शुरू करने समेत सरकार ने एक साल 22 नियुक्ति परीक्षाएं रद्द कर सांख्यिक निर्णय लिया

झारखंड डायरी

है। इतना ही नहीं, वर्ष 2014 से हुई तमाम नियुक्ति परीक्षाएं भी सीआईडी के जांच के खारे में आ गई हैं। आंदोलन के दौरान चले छात्रों ने शांतिपूर्ण ढंग से अपना विरोध-प्रदर्शन किया और इसमें धरना, भूख हड़ताल जैसे सत्याग्रह के तरीके अपनाए, वहीं सरकार ने भी छात्रों की बातों को पूरी गंभीरता से सुना और उनकी मांगों को मानने के साथ ही तमाम छात्रों और युवाओं के प्रति संवेदनशीलता दिखाई।

परीक्षा व्यवस्था का बदला जाना आनेवाले दिनों में अगर सरकार सखित हुआ तो नियुक्ति परीक्षाओं में धोखाड़ी और अनियमितताओं की गुंजाइश कम रहेगी, जिससे प्रतिभाशाली छात्रों के साथ न्याय हो सकेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सांख्यिक और एंजेलिस्टिक कदम उठाया जो उनकी छात्रों के हित के प्रति उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति, उनकी दृढ़दृष्टि और परिपक्वता को परिलक्षित करता है। अब तक के झारखंड के इतिहास में ऐसा पहला निर्णय लिया गया कि सीजीएल



मौरी पूरे होने के बाद रांची में आमर यात्रा निकालते आंदोलनकारी छात्र। फाइल

समेत 22 परीक्षाओं को एक साथ रद्द करने तथा छठ को अगले आदेश तक के लिए स्थगित करने अधिसूचना जारी की गई। इस कड़े फैसले का दूसरा पहलू यह है कि सीजीएल (संयुक्त स्नातक स्तरीय) नियुक्ति परीक्षा और 11वीं से 13वीं जेपीएससी स्तित्व सेव परीक्षा समेत नई परीक्षाओं के माध्यम से नियुक्त होकर नौकरी कर रहे सैकड़ों

असरर और कर्मचारियों की नियुक्तियां प्रभावित हो गईं। ऐसे कर्मचारी और असरर अब प्रदर्शन कर सरकार से नियुक्तियों रद्द करने का निर्णय वापस लेने की मांग कर रहे हैं। हालांकि इस बीच ऐसे लोगों की याचिका पर सुनवाई करती हुई हाई कोर्ट ने सरकार के निर्णय पर तत्कालीन कर लगा दी है, जिससे उन्हें राहत मिल गई है। दूसरी सरकार

की लगातार यह कह रही है कि निम्नकी नियुक्तियों में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, ऐसे लोगों के लिए भी उचित रास्ता निकालने का प्रयास होगा।

सरकार ने पूर्व प्रकरण में बहुत सुझावों से काम लिया। लगातार मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल आंदोलनरत छात्रों से बातचीत कर रहा था और हल निकालने का प्रयास कर रहा था। अंततः 17 अगस्त को खुद मुख्यमंत्री आगे आए और कैबिनेट की बैठक कर छात्रों के हित में निर्णय लिया। इस कदम का छात्रों ने स्वागत किया। सोमवार की देर शाम जब प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रेस से वार्ता कर रहे थे तब पूरा राज्य उन्हें न्याय से सुन रहा था। उन्होंने न सिर्फ छात्रों की बातें मांग लीं, बल्कि छात्रों की मांगों से आगे बढ़कर ऐसी सभी नियुक्ति परीक्षाएं रद्द कर दीं, जिसमें लेकर कोई भी संदेह या विवाद है। छात्रों ने भी सरकार के इस कदम का स्वागत किया और इस निर्णय के बाद आगर यात्रा निकालकर आंदोलन

को स्थागित कर दिया। छात्रों के कुछ सौजन्य अभी गड़बड़ीयों की सीबीआई जांच करने की मांग दोहरा रहे हैं। लेकिन सीआईडी जांच के प्रेम में ही जिस तरह से जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एन डियारने समेत दो दर्जनों से अधिक लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर सरकार ने कड़े तवर दिखाए, उससे युवाओं का बढ़ा गुंथ संघट्ट दिख रहा है। हेमंत सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि युवाओं के भविष्य से छिलवाए करने वाले और भ्रष्टाचार करवाले किसी भी आरोपित को इस पर सरकार में सरकार बखाने वाली नहीं है। यह कहा जा सकता है कि इस मामले में सरकार ने दो कदम आगे बढ़कर कड़े निर्णय लिए। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिस निर्णय से कुछ अचर्यधर्मी की नीकरी हुई है, उससे उलट एलिए और यह निकलने के लिए प्रयास में लगी है, लेकिन, जिन लोगों ने छात्रों के भविष्य से छिलवाए किया गया है, उन्हें जेल जाने से कोई बचा नहीं सकता।

खरी-खरी

डायरी से स्टेटस तक का सफर

राजेंद्र कुमार सिंह

समय के साथ आदमी के विचार भी बदलते रहते हैं। कभी वह दौर था, जब हम कोई भी कार्य करते थे तो आमजन तो दूर की बात, अपने घर के सदस्यों से भी अपने विचारों को छिपाकर रखते थे। उन्हें डायरी के पन्नों पर लिखकर सुरक्षित रख लेते थे, ताकि परिवार में जब कभी अनिर्णय आती तो टटोलने की जरूरत पड़े तो उस समय और उस दिन का सही-सही आलेखन किया जा सके।

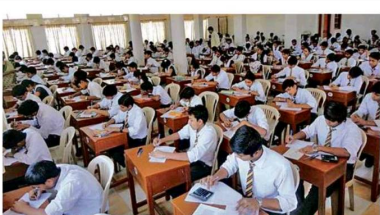
लेकिन जैसे-जैसे वक्त कस्टर लेता गया, हमारे आचार-विचार और बात-व्यवहार में उमका प्रभाव पड़ता गया। वक्त जिस प्रकार रह पर आगे बढ़ रहा था, उसी के साथ आम लोगों की सोच भी बदलती चली गई। मैं भी कभी इसी सिद्धांत को अपने जीवन में उतारकर निरंतर आगे बढ़ रहा था। अपने विचारों को अपने क सीमित रहना ही बेहतर समझता था।

आज के दौर पर अगर गौर करें तो शाहद ही कोई इस्त्रो अहूता रह गया हो। जो विचार कभी हम अपने तब छिपाकर रखते थे, इंटरनेट मीडिया के प्रसार की वजह से उन्हें ऐसी गति दे दी है कि बारिश की हल्की फुहार पड़ते ही चारों ओर फैल जाता है। हमारा जो विचार कभी संकुचित होकर हमारे भीतर कैद रहता था, आज वह स्वतंत्र होकर बाहर निकलने में विचरण कर रहा है।

हालांकि निजी जिंदगी माने एक खुली किताब बन गई है, जिसका कोई भी व्यक्ति कभी भी कोई पन्ना पलटने की कोशिश कर सकता है।

पहले हमारे विचार डायरी के पन्नों में कैद होकर किसी क्षण में पड़े रहते थे। ये हमारे उजड़ते थे-न पड़े रहते। लाइक की चिंता, न कमेंट की प्रतीक्षा और न ही किसी के खेद का डर। आज बंधी विचार डायरी से निकलकर स्टेटस बन गए हैं। अब वे खुलेआम विवरित हो रहे हैं और हम प्रत्यक्ष से इनकार करते हैं कि इस बार हमारी जिंदगी का कौन-सा पन्ना लोगों को सबसे ज्यादा दर्द पहुंचा है।

क्या पसंदी आता तो नहीं बदले, क्या उन्हें पढ़ते वाले बदल दिए। पहले हम अपने विचार लिखकर छिपाते थे, आज लिखकर दुनिया को दिखाने का इशारा है-डायरी से स्टेटस तक का सफर।



परीक्षा व्यवस्था को तकनीकी से जोड़कर परी लीक पर निगरानी का हो रहा प्रयास। फाइल

विवरसनयता और छात्रों का संदेह निरुद्धितों में कोई गड़बड़ीयों की सीबीआई जांच करने की मांग दोहरा रहे हैं। लेकिन सीआईडी जांच के प्रेम में ही जिस तरह से जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एन डियारने समेत दो दर्जनों से अधिक लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर सरकार ने कड़े तवर दिखाए, उससे युवाओं का बढ़ा गुंथ संघट्ट दिख रहा है। हेमंत सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि युवाओं के भविष्य से छिलवाए करने वाले और भ्रष्टाचार करवाले किसी भी आरोपित को इस पर सरकार में सरकार बखाने वाली नहीं है। यह कहा जा सकता है कि इस मामले में सरकार ने दो कदम आगे बढ़कर कड़े निर्णय लिए। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिस निर्णय से कुछ अचर्यधर्मी की नीकरी हुई है, उससे उलट एलिए और यह निकलने के लिए प्रयास में लगी है, लेकिन, जिन लोगों ने छात्रों के भविष्य से छिलवाए किया गया है, उन्हें जेल जाने से कोई बचा नहीं सकता।

विवरसनयता और छात्रों का संदेह निरुद्धितों में कोई गड़बड़ीयों की सीबीआई जांच करने की मांग दोहरा रहे हैं। लेकिन सीआईडी जांच के प्रेम में ही जिस तरह से जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एन डियारने समेत दो दर्जनों से अधिक लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर सरकार ने कड़े तवर दिखाए, उससे युवाओं का बढ़ा गुंथ संघट्ट दिख रहा है। हेमंत सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि युवाओं के भविष्य से छिलवाए करने वाले और भ्रष्टाचार करवाले किसी भी आरोपित को इस पर सरकार में सरकार बखाने वाली नहीं है। यह कहा जा सकता है कि इस मामले में सरकार ने दो कदम आगे बढ़कर कड़े निर्णय लिए। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिस निर्णय से कुछ अचर्यधर्मी की नीकरी हुई है, उससे उलट एलिए और यह निकलने के लिए प्रयास में लगी है, लेकिन, जिन लोगों ने छात्रों के भविष्य से छिलवाए किया गया है, उन्हें जेल जाने से कोई बचा नहीं सकता।

परीक्षा परीक्षा का मुद्दा सरकार और आयोग की निगरानी में सरकारी एजेंसियों द्वारा किया जाना चाहिए। परीक्षा परीक्षा की सुरक्षा के लिए डिजिटल

मैंने सीखा है कि लोग ये भूल जाएंगे कि आपने क्या कहा। लोग ये भी भूल जाएंगे कि आपने क्या किया। मगर ये यह कभी नहीं भूलेंगे कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया।
- माया एंजिलो

कूटनीतिक संदेश

भारत में अमेरिका के राजदुत सर्जियो गोर ने जम्मू-कश्मीर के बारे में जो यात्रा जाहिर की है, उसकी अपनी अहमियत है। खालतीपर पर अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में अमेरिका को जिस नजर से देखा जाता है, उसमें उसकी प्रतिक्रिया को किसी पक्ष या विपक्ष को मिलने वाले महत्व की नजर से देखा जाता है। ऐसी स्थिति में अमेरिका के राजदुत के रूप में सर्जियो गोर ने जिस तरह जम्मू-कश्मीर को भारत का एक 'महत्त्वपूर्ण हिस्सा' बताया, उसे इस मुद्दे पर अमेरिका के बदलते रुख के संकेत के तौर पर भले देखा जा रहा हो, लेकिन यह संवात भी उठा है कि उनका यह बयान भारत के लिहाज से कितना अहम है। इसके अलावा, गोर ने जम्मू-कश्मीर के लिए जारी अमेरिकी यात्रा परामर्श की सीमाओं करने की भी बात कही। दरअसल, कूटनीति की दुनिया में कई बार शब्दों की वारिकियों के जरिए जिस परिदृश्य की रचना की जाती है, उसका अंदाजा प्रभाव के स्तर से लगा पाता है। ऐसे में जो जम्मू-कश्मीर बिना किसी संवात के भारत का अभिन्न हिस्सा है, उसके बारे में सर्जियो गोर को अलग से कुछ राय जाहिर करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? फिर 'अभिन्न हिस्सा' के बजाय 'महत्त्वपूर्ण हिस्सा' बताने को भारत में किस नजर से देखा जाएगा!

गौरतलब है कि अमेरिका पारंपरिक तौर पर जम्मू-कश्मीर के मामले को भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय बातचीत के जरिए सुलझाने का हामी रहा है। यही नहीं, एकाध भूमिका पर अमेरिका ने कश्मीर मामले में मध्यस्थता की भी भूमिका निभायी की पेशकश की थी, लेकिन भारत ने उसे खारिज कर दिया था। यों कोई संदर्भ भी चूँकि पाकिस्तान को लेकर अमेरिका की दृष्टि में अलग एक अप्रत्यक्ष तर्फी दिखाई देती रही है और परिणाम फलित में युद्ध के बीच पिछले कुछ समय से दोनों के बीच थोड़ी करीबी बढ़ती देखी गई है, इसलिए इस बात की आशंका हो सकती है कि अमेरिका का रुख कुछ कई बार जरूरत और सुविधा के मुताबिक भी संश्लिप्त होता है। ऐसे में यह देखने की जरूरत होगी कि गोर के बयान के बाद पाकिस्तान ने जिस तरह तीखी आपत्ति जाहिर की है, उसमें अमेरिका आगे क्या रुख अपनाता है। इसमें कोई दोराय नहीं कि भारत में जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर किसी अन्य देश को किसी भी स्तर पर देखल देने की जरूरत नहीं है। इस मसले पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र सहित समूची दुनिया में स्थिति बिलुलत रम्य करके रखी है। इसके बावजूद समय-समय पर जम्मू-कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की ओर से नाहक खललपूर्ण और बयानबाजी करके एक नकारात्मक संदेश देने की कोशिश होती रही है।

पिछले कुछ सालों के दौरान चंद उबार-चढ़ावों को छोड़ दिया जाए, तो जम्मू-कश्मीर में अमामती पर शांति और स्थिरता आती देखी जा रही है। इसलिए यह सच है कि पाकिस्तान की ओर से तमाम नकारात्मक कवायदों के बावजूद यह देश के बारे में वैश्विक स्तर पर अलग राय बनी है। यही वजह है कि सर्जियो गोर के बयान को भारत के प्रति अमेरिकी नीति या दृष्टि में बदलाव के एक संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है। हालाँकि यह भी गौरतलब है कि गोर का बयान भारत के पक्ष में झुका हुआ लगता है, लेकिन जम्मू-कश्मीर को भारत का 'अभिन्न हिस्सा' के बजाय 'महत्त्वपूर्ण' हिस्सा बताना एक सुविधा की कूटनीति भी हो सकती है। यों भारत को जम्मू-कश्मीर के संदर्भ में किसी तीसरे पक्ष की दिलचस्पी को फिलहाल सतर्क होकर ही देखने की जरूरत है।

जोखिम में बच्चे

पिछले कुछ वर्षों से आभासी दुनिया में बच्चे जिस तरह मग्न हो गए हैं, वह देखते हैं, वहाँ से उनको निकालना एक बड़ी चुनौती है। आज पूरे विश्व में करोड़ों बच्चे सोशल मीडिया की लत से प्रभावित हैं। वे न केवल समाज से, बल्कि परिवार से भी कट गए हैं। सराल है कि यह आदत उठ गई लगी या लगाई गई? आज आभासी दुनिया में विविध मंच उपलब्ध कराने वाली मेटा इस मुद्दे पर कटघर में है। गौरतलब है कि अमेरिका के चार राज्यों ने इसके संचालन में बदलाव की मांग की है। बच्चों की सुरक्षा और निजता पर उठ रहे संवात वेद गंभीर प्रकृति के हैं और उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। संबंधित राज्यों ने मेटा के खिलाफ संघीय अदालत में आरोप लगाया है कि उसने अपने आप इस तरह बनाए हैं कि वे बच्चों को आदी बनाए और उन्हें ज्यादा समय तक रोकें रखें तथा उनका डेटा जमा करें। मेटा तेरह वर्ष से कम उम्र के बच्चों का अभिवाचन की सहमति के बिना डेटा जमा करती है, जो संघीय कानून का उल्लंघन है। हालाँकि मेटा ने अपना बयान किया है, लेकिन उसकी दलीलें कमजोर दिखाई दे रही हैं।

सवाल है कि अगर मेटा के विविध मंचों पर बच्चों की उपस्थिति अप्रत्याशित तरीके से बढ़ रही थी, तो उसे सहज क्यों मान लिया गया और समय रहते जरूरी कदम क्यों नहीं उठाए गए? यों मेटा समय-समय पर अनुभव को सुश्लिष्ट बनाने वाली सुविधाएँ शुरू करने की बात कहती रही है, लेकिन सच यह है कि वे सुविधाएँ कभी प्रभावी नहीं थीं। इस समय विविध मंचों पर जिस तरह की सामग्री परेशी जा रही है, उसे रोकने के किसी स्तर पर प्रयास नहीं दिखाता। मेटा की मुश्किलें कम होती इसलिए नहीं दिखती रही हैं, क्योंकि उस के एक पूरे अधिकारी ने गवाही दी है कि कंपनी ने अपने मंचों से कम उम्र के बच्चों को लेकर 'पूछो मत, बताओ मत' वाले संदेश को अपनाया और सुरक्षा की तुलना में मुनाफे को प्राथमिकता दी। अब मेटा जो भी सफाई दे, लेकिन यह सच है कि बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर इसका नकारात्मक असर पड़ा है। संघीय अदालत में चल रहा मुकदमा इसलिए भी अहम है कि इस पर पूरी दुनिया की नजर है। यह मुद्दा करोड़ों बच्चों के भविष्य से जुड़ा है।

जनगणना के समाप्तर जलवायु का संवात



कुशाग्र राजेंद्र

देश एक बार फिर जनगणना की तैयारी में है। लंबे अंतराल के बाद होने वाली यह जनगणना स्वाभाविक रूप से अनेक प्रश्नों के केंद्र में है। क्या इसमें जातिगत गणना होगी? इससे कल्याणकारी योजनाओं और राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? राज्यों की संसंधानों का बंटवारा किस आधार पर होगा? ये सभी सवाल महत्त्वपूर्ण हैं और लोकतांत्रिक विमर्श का हिस्सा भी, लेकिन इनके बीच एक बुनियादी सवाल लगातार अनुपस्थित है और यह कि क्या इक्वीसरी सभी की जनगणना उन वास्तविकताओं को दर्ज करने के लिए तैयार है, जिनका खामना आज का भारत कर रहा है? जनगणना प्रयास केवल आवासीय निम्न की प्रक्रिया मानी जाती है। जबकि यह किसी भी राष्ट्र की प्रशासनिक दृष्टि का दर्पण होती है। कोई भी सरकार जिन बातों को जानना आवश्यक समझती है, वही उसके प्रश्नों में दिखाई देती है। जनगणना केवल यह नहीं बताती कि देश में कितने लोग हैं, बल्कि यह भी बताती है कि राज्य अपने समाज को किस नजर से देख रहा है और भविष्य की चुनौतियों को किस प्रकार समझना चाहता है। स्वतंत्र भारत की जनगणना समय के साथ बदलती रही है। आवास, पेयजल, सौचालय, बिजली, रोजी रोटी, बैंकिंग सुविधा, स्वास्थ्य फोन और इंटरनेट जैसी जानकारियाँ इन्में क्रमशः जुड़ती गईं। इनसे शासन को विकास योजनाएँ बनाने, सामाजिक असमानताओं को समझने और समाज की आवश्यकताओं को लक्षित करने में बड़ी सहायता मिली। इसमें कोई संदेह नहीं कि आधुनिक भारत के निर्माण में जनगणना ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज भारत जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है, वे केवल सामाजिक या आर्थिक नहीं हैं। जलवायु परिवर्तन अब भविष्य की आशंका नहीं, बल्कि आज की वास्तविकता है। उरर भारत में तीव्र हो रही चु, भीषण मौस, पूर्वी भारत में आकाशीय बिजली गिरने की बढ़ती घटनाएँ, असम और बिहार में बार-बार आने वाली बाढ़, बुंदेलखंड और पश्चिम में गहलता जल संकट, हिमालयी क्षेत्रों में भूस्लान और हिमनद झिल्ली के फटने का खतना तथा पश्चिमी भारत में भूजल का लगातार गिरता स्तर, ये सभी घटनाएँ अब अलग-अलग पर्यावरणीय समस्याएँ नहीं रही। इनका सीधा असर खेती, रोजगार, स्वास्थ्य, पेयजल और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है।

विश्वना यह है कि इन परिवर्तनों को समझने के लिए हमारे पास अलग-अलग विचारों में बहुत-सी सुचनाएँ उपलब्ध हैं, लेकिन वे एक-दूसरे से जुड़ती नहीं हैं। मीसम का आंकड़ा एक संस्था के पास है, भूजल का दूसरे के पास, कृषि का तीसरे के पास और जनसंख्या का चौथे के पास। परिणाम यह है कि हमें यह तो पता है कि किसी गाँव में कितने परिवार रहते हैं, लेकिन यह व्यवस्थित रूप से नहीं पता कि सुखाने वाला, घटा भूजल, बदलती फसलें या बार-बार आने वाली आपदाएँ वहाँ के लोगों के जीवन और आजीविका को किस प्रकार बदल रही हैं। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में सामूहिक केवल आंकड़ों की कमी नहीं है। समस्या यह है कि हमारे पास जीवन और पर्यावरण को एक साथ देखने वाली सूचना व्यवस्था नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि भारत के प्रशासनिक इतिहास में ऐसी समग्र दृष्टि के



उदाहरण पहले से मौजूद है। इसका एक उदाहरण 1887 में तत्कालीन मराठवाड़ा राज्य में जनगणना के लिए तैयार की गई प्रमाणपत्र है। यह केवल गाँव की आबादी या राज्य का व्योग भर नहीं माँगी थी। इसमें कुओं और तालाबों की संख्या, पानी की गुणवत्ता, मिट्टी का प्रकार, चरागाह, वृक्षों की प्रजातियाँ, मनुष्य,

आज भारत जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है, वे केवल सामाजिक या आर्थिक नहीं हैं। जलवायु परिवर्तन अब भविष्य की आशंका नहीं, बल्कि आज की वास्तविकता है। उरर भारत में तीव्र हो रही चु, भीषण मौस, पूर्वी भारत में आकाशीय बिजली गिरने की बढ़ती घटनाएँ, असम और बिहार में बार-बार आने वाली बाढ़, बुंदेलखंड और पश्चिम में गहलता जल संकट, हिमालयी क्षेत्रों में भूस्लान और हिमनद झिल्ली के फटने का खतना तथा पश्चिमी भारत में भूजल का लगातार गिरता स्तर, ये सभी घटनाएँ अब अलग-अलग पर्यावरणीय समस्याएँ नहीं रही हैं। इनका सीधा असर खेती, रोजगार, स्वास्थ्य, पेयजल और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है।

स्थानीय फसलें, कुदरत उद्योग, महामारी, अकाल, पलान, स्थानीय परतोर और गाँव की सामाजिक संस्थाओं तक का विवरण दर्ज करने के 56 प्रश्न थे। गाँव

सुप्रिया सत्यार्थी

हमारे समाज में कुछ परंपराओं को लोग सही मानना इसलिए शुरू कर चुके हैं, क्योंकि वे पुरानी हैं। उनके औचित्य पर सवाल उठाना तो दूर, यह पछुता भी जरूरी नहीं समझा जाता है कि इसके साथ ही होता है, उसका आधार क्या है। विचार और दूसरे शुभ अवसरों से जुड़ी कई मान्यताओं को इस श्रेणी में देखा जा सकता है। आज भी समाज के कुछ हिस्सों में यह धारणा दिखाई देती है कि पति को अपनी स्त्री शुभ अवसरों से दूरी बनाना चाहिए। उसकी उपस्थिति तक को अपशकुन की दृष्टि से देखा जाता है। समकाल एक रम्य का नती है। सवाल यह है कि क्या पति की मृत्यु के साथ एक स्त्री सामाजिक रूप से शुभ नहीं रह जाती? अगर ऐसा है तो फिर उस स्त्री के जीवनपर के संबंध का मूल्यकन किस आधार पर होगा? वह माँ, जिसने अपने बच्चों को अकेले बड़ाया और पति की अनुपस्थिति में घर और बाहर, दोनों में माँ संभाला। उसने अपने बच्चों को पीछे रखकर बच्चों की पढ़ाई, नींद, विद्या और श्रद्धा के लिए जीवन खपा दिया। बीमारी, आर्थिक संकट, सामाजिक दबाव और अकेलेपन के बावजूद बच्चों को टूटने नहीं दिया। क्या वह स्त्री केवल इसलिए अप्रभु हो गई कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं है? यहाँ हमारी सामाजिक मानसिकता का एक गहरा विरोधाभास सामने आता है। पति जीवित है, तो वह सुखान और शुभ है। पति की मृत्यु के बाद वह स्त्री अचानक ऐसी श्रेणी में रख दी जाती है, जहाँ उसे कुछ लोग शुभ अवसरों के लिए अनुपयुक्त मानते हैं।

वे केवल अंधविश्वास नहीं, स्त्री की पहचान को पुरुष से जोड़कर और उस पर निर्भर देखने वाली उस मानसिकता का विवर्तन है, जो सदियों से हमारे सामाजिक ढांचे में मौजूद रही है। विडंबना यह भी है कि जिस स्त्री को पति की मृत्यु के बाद सबसे अधिक सहारे की आवश्यकता होती है, उसी समय समाज उसके चारों ओर कई अदृश्य दीवारें खड़ी कर देता है। उससे अपेक्षा की जाती है कि वह अपने दुःख को निजी रखे, सामाजिक जीवन में संयमित रहे। कल्याण कीर्तिज उन माँ को, जिसने अपने बेटे या बेटों की हर छोटी-बड़ी खूबियों में अपना जीवन लगा दिया। उनके बचपन से युवावस्था तक हर पल पर देखा और जब वही बच्चा विवाह के मंडप तक पहुँचा है, तब माँ को यह एहसास करया जाता है कि वह कुछ रस्मों का हिस्सा बनने के योग्य नहीं है। तब माँ क्या महसूस करती होगी? शावद वह कुछ कहे भी नहीं, क्योंकि हमारे समाज ने महिलाओं को दर्ज सनना तो सिखाया है, लेकिन अपने दर्ज पर सवाल उठाना नहीं। और यही चुपचाप इन परंपराओं को जीवन भरती है।

किसी महिला का पति नहीं रहा, तो वह उससे जीवन की त्रासदी है, उसकी पहचान नहीं। मृत्यु किसी रिस्ते को समाप्त कर सकती है, जिस परंपरा को बचाने के लिए किसी माँ या किसी स्त्री को समाज को वास्तविक प्रगति है। यह भी जरूरी है कि इस प्रश्न को केवल महिलाओं का प्रश्न मानकर छोड़ न दिया जाए। यह पूरे परिवार और समाज का प्रश्न है। हमने समाज में अनेक कुरीतियों पर प्रश्न उठाए हैं। बाल विवाह, स्तरी प्रथा, दहेज, अश्वस्थता और स्त्री शिक्षा से जुड़े अनेक प्रश्न हमारे चुनौती दी गई। आज माँ समाज तब प्रतिनिधित्व करारण, जब वह उन अदृश्य भेदभावों पर भी सवाल उठाए, जो धार्मिक या सांस्कृतिक आड में अब तक बचे हुए हैं।

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupai.jansatta@expressindia.com

नाकाम बीबी प्रबंधन

बिहार के लखीसराय स्थित अशोकधाम मंदिर में पिछले दिनों हुई भारदूत न एक बार फिर भी प्रबंधन को लेकर गंभीर संवात खड़े कर दिए हैं। बिहार में कुछ मंदिरों पहले नालंदा स्थित एक मंदिर में भी ऐसी ही त्रासदी हो चुकी है। तब भी वहाँ प्रेष प्रेष करण पर सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए व्यवस्था मजबूत करने की जरूरत महसूस हुई थी। मगर संवात यही है कि हानि के बाद बचने वाली योजनाएँ अभीपर निष्पत्ती उतरती हैं। जिन किसी विशेष पर्व या अर्वा धार्मिक अवसर पर सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक ब्रह्मदुओं के पहुँचने का संभावना पहले से जमाना होती है, तो उसे धर्म में रखते हुए प्रेष, निगरा, अशोकधाम, आपातकालीन प्रेष, चिकित्सा सुविधा और अग्नाहोरी से निपटने की व्यवस्था क्यों नहीं हो पाती? पिछले दो वर्षों के घटनाक्रम को देखें, तो देश के अलग-अलग हिस्सों में धार्मिक आयोजनों के दौरान भी वही दवाव कई बार जालेला प्रमाण हुआ है। भीड़ प्रबंधन अपने आप में बड़ी चुनौती होती है। इस हानि से निर दिखाना कि लखी-करोड़ों लोगों की आस्था के बीच एक छोटी-सी अव्यवस्था भी गंभीर परिणाम दे सकती है।



- काविलत मांडीत, लखनऊ

भरोसे का सवाल

पेट्रोलियम मंत्रालय का तर्क है कि ई-20 वैज्ञानिक रूप से स्वीकार्य है। आठोपेरावल उद्योग में देशभर में पेट्रोल पंप, रिफाइनरी, डिपो और पाइपलाइन नेटवर्क में अलग-अलग प्रेड (शुद्ध पेट्रोल, ई-10 और ई-20) की आगुपि भूखला बनाना भारी लाजिस्टिक चुनौती प्या करना। मंत्रालय का कलना है कि ई-20 से कच्चे तेल के आयात बिल में कमी आगुपी और यह ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम

मुआवजा का आधार

कृतिक आपदाएँ हों या मानवीय भूत से होने वाली दुर्घटनाएँ, प्रत्येक वर्ष हजारों परिवार इनके दुष्परिणाम झेलते हैं। आठोपेरावल अस्मय मनुष्य का शिकार होता है, तो कोई जीवनपर के लिए गंभीर रूप से बाध हो जाता है। ऐसे संकट की घड़ी में सरकार की ओर से दी जाने वाली आर्थिक सहायता पीडित परिवार के लिए संवात होती है। वर्तमान संविधान में क्षतिपूर्ति की शर्त राज्यों, पंचनाम के स्वरूप, सरकारी नियमों तथा कभी-कभी

इच्छाशक्ति का तकाजा

रखंड में हाल में ही हुई 14वीं जेपीएससी परीक्षा के मुद्दे पर छात्र आंदोलन से बने दवाव के बाद सरकार ने छात्रों की सखर माँग को मान लिया। छात्र आंदोलन जारी रहने के कारण सरकार सरकार के सामने शारद्वक्ष माँची, काँग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन के राजनीतिक भविष्य को खतरा में पड़ना देख कर जायम माँग को मानने की विवशता हो गई। वही दूसरी ओर, जेपीएससी-सीएलए परीक्षा रह करने में देरी होने पर सरकार की साख भूमिल होने के आसार नजर आने लगे। जेपीएससी-सीएलए परीक्षा में हुई अनियमितताओं को लेकर सीआईडी जांच में तेजी आई है। इसलिए जांच होने तक दूध का दूध और पानी का पानी होने तक संबंधित को की राजनीतिक हानि और लाभ से ऊपर उठ कर काम करना चाहिए।

- युगल किशोर शर्मा, फरीदाबाद

हिन्दुस्तान

राष्ट्रगीत के लिए

राष्ट्रगीत *वंदे मातरम्* पर छिड़ा विवाद दुखद और गैर-न्यायिक है। काश ! इस मामले में राजनेताओं में परस्पर सहमति बन गयी, तो अनावश्यक चर्चा को बल नहीं मिलता। इसमें कोई दोषय नहीं कि यह गीत हमारे स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण प्रेरणा स्रोत रहा है। पिछली सदी की शुरुआत से ही कांग्रेस के अधिवेशनों में भी इसे तनी-तनक तक पूरा और निरंतर गाया जाता था। जब देश में सांसादनिक तनाव के हालात बनने और बढ़ने लगे, तब कांग्रेस के आला नेतृत्व ने साल 1937 में राष्ट्रगीत के दो पैरा को ही गाने का फैसला लिया था। आज भी शायद सिधायी वजहों से कांग्रेस उसी फैसले पर चलना चाहती है, लेकिन ध्यान रहे, आज कांग्रेस को चुनौती देने के लिए भारतीय जनता पार्टी बहुत सशक्त स्थिति में है। आरम्भ नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के फैसले को तीखी आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि वह अपनी तुट्टीकरण की नीति को पुनर्जीवित कर रही है। वाकई, यह इतिहास में दर्ज है कि साल 1937 में *वंदे मातरम्* के तन के आधे से आधे हिस्से को नियमित गायन से अलग कर दिया गया और ठीक दस साल बाद भारत को बंटने से नहीं रोका जा सका।

अब केंद्र सरकार ने चाणक्यवाद का नया नकाश यह कोशिश की है कि *वंदे मातरम्* गीत को पूरा गाया जाए। नए प्रोटोकॉल के तहत, निर्धारित सरकारी कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत का छह पैरा या शेलोकी वाला पूरा संस्करण गाया जाएगा, जिसकी अवधि 3 मिनट 10 सेकेंड है। देश को प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस इसे नहीं मानना चाहती है, उसने राष्ट्रगीत के केवल पहले दो श्लोक गाने का निर्णय लिया है। ऐसे में, केंद्रीय गृह मंत्री का यह कलम विचारणीय है कि पिछली पार्टी का यह निर्णय केवल प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि उस एंटीहासिक त्रुटि को पुनरावृत्ति है, जिसके कारण भारत का विधानमंडल हुआ था। देश में जो लोग *वंदे मातरम्* को पूरा गाने के पक्ष में हैं, उन्हें कांग्रेस का ताजा निर्णय चौंका रहा है। वैसे, कांग्रेस का निर्णय अब भी 15 अगस्त

आज भी शायद अनेक वजहों से कांग्रेस सन् 1937 के फैसले पर चलना चाहती है, लेकिन आज उसे चुनौती देने के लिए भाजपा बहुत सशक्त है।

के आयोजन में *वंदे मातरम्* के गायन के समय जो विवाद देखेंगे, उसके बाद लिया गया कांग्रेस का यह फैसला उसकी अपनी 1937 के बाद की नीति के अनुरूप ही है। हालाँकि, इस फैसले का राजनीतिक विरोध तब है और जबकि वंदे के लिए कांग्रेस को येवार सत्ता चाहिए। काश ! मजबूत को बुनियाद पर बंटवारा न हुआ होता, तो 1937 में कांग्रेस नेताओं द्वारा लिया गया फैसला आज मील के पथर या एक निर्णायक गौरवशाली मोड़ की तरह होता। स्वतंत्र भारत की मूल नीति सबको खुश करने की रही है और आगे भी रहेगी, लेकिन अफसोस, बंटवारा को भुलना बहुत मुश्किल है। यह एक ऐसा अध्याय है, जिसके पन्ने अक्सर सिधायी हवा पाकर लहराने लगते हैं। खैर, अब तो भारतीय संसद में अधिनियम बन गया है कि *वंदे मातरम्* को पूरा गाया जाएगा। यह अधिनियम भारतीय संविधान का हिस्सा है और भारतीय संविधान का सम्मान हर हाल में होना चाहिए। सम्प्रदाय में देखें, तो यह विषय विगत मानवानुसार है, उनका ही राजनीति नहीं है। यहाँ देश के आम लोग को पूरी संवेदना और वैचारिक संतुलन के साथ विचार करना चाहिए। यह *वंदे मातरम्* गीत का 150वाँ वंश है और यह गीत के सम्मान को परंपरा में जगमगाती चाली है। यह अकादमिक रूप से कि हमारा राष्ट्रगीत एक श्रेष्ठतम अभिव्यक्ति है और इसके यथोचित आदर में हम भारतवासियों का सम्मान निश्चित है। यह आधिकारिक राष्ट्रगीत सबसे सदाय की आशा रखता है।

हिन्दुस्तान 15 साल पहले 21 अगस्त, 1951

ईराकी खजूर

भारतीय संसद में जो सिधायी ने ईराकी खजूर की चर्चा उठाई थी और इस पर खाद्य मंत्री श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्शी ने जो स्पष्टीकरण दिया, उससे प्रकट होता है कि सरकार को व्यापारियों ने किस प्रकार राज ठीक पाना चाहता था। देश में यह खजूर की कमी पड़ गयी थी तो सरकार ने उसकी पूर्ति करने के लिए दो बार कच्चे 26 हजार टन खजूर का ईराक से आयाज किया। श्री मुन्शी ने बताया कि यह खजूर अचौ की क्लिम की थी और सरसों भी था। फिर यह बिक नहीं सका और नरबई और मध्य प्रदेश की सरकारों को क्रशर 2 लाख 20 हजार और 4 लाख 80 हजार बावरी ग्राहक खजूर की हात जितानी पड़ी। श्री मुन्शी के बयान में खजूर के न किये जाने कारण यह रहा कि नरबई के व्यापारियों के एक शिफारशीदार ने जान-बूझकर यह झूठी अफवाह फैला दी थी कि सरकार द्वारा आयाज की हुई खजूर का ईराक से आयाज किया जा रहे था कि सरकार को खजूर की कमी नहीं थी। व्यापारियों का उद्देश्य यह था कि उन्हें अपना बाल बेचने का अवसर मिल जाय और व्यापारियों ने 13000 हलकी क्लिम की खजूर के टोकेन बेच जाले और सरकारी भावना को धुँधला दिया। श्री मुन्शी ने पड़ा-पड़ा यह बताया। आश्चर्य की बात यह है कि सरकारी माल का मरफा साहेब तभी आना और फौज तैनात आना प्रति रण था, जबकि व्यापारियों ने अपना माल एक प्रेष गति से रण भिडायो से चले।

व्यापारियों का नैतिक स्तर इन दिनों किशन अधिक रण था, इसका यह एक अच्छा उदाहरण है। इस पृष्ठ में ज्ञान देश में व्यापारी को बाल बेचने के लिए पैसे में धुंध का आश्रय लिये बिना काफ़ी बाल बेच ही नसकता। उनकी लोभजुति बहद यह थी और उसे समर्थन देने के लिए नीति की सीमा गाँव को उड़ोने पर उलटता ताक में रहा दिखता है। पुराने जमाने में व्यापारी धर्म को बखरा खाल रखते थे। अपने काम को उल्टा-काँट समझकर करते थे। जो वास्तव एक पक्ष पर उलटव नहीं होता, उसे दूसरे पक्ष से लाकर बेचते थे और अपने परिश्रम का निर्दिष्ट और उचित वेतन प्राप्त करने के समुदाय हो जाते थे। बुरी बल्लू को अच्छा बालकर बेचना, शाक के अन्न का फायदा उठाकर अंधाधुंध मुनाफा आसना और धुंध का आश्रय लेकर अपने प्रतिद्वंद्वियों को पहाड़ाना आज सामान्य हो गया है। किन्तु प्रसुत उदाहरण में बम्बई के व्यापारियों ने सरकार को भी नहीं छोड़ा है।

अशालीन पहनावे पर नियंत्रण जरूरी

दिल्ली उच्च न्यायालय में एक वकील ने जब यह तर्क दिया कि 'लड़की ने जींस और टॉप क्यों पहना था' तो न्यायाधीशों ने 'तो न्यायाधीशों ने देखा था कि आपात जमाने हुए सफा साफ कि किसी महिला के कपड़े उसकी नीति पर हैं। यह क्या पहनती है कि पहने पाइलोट, सामान, वहाँ तक कि किसी वकील का भी मामला नहीं बनता है। कपड़ों को आधार बनाकर किसी रन-रन हरलत को कानूनी नहीं ठहराया जा सकता।

यह वाक्या उत्र समझ का है, जब उच्च न्यायालय में वीन उन्नीइए के एक मामले की सुनवाई हो रही थी। बचाव पक्ष की ओर से खड़े वकील का यह तर्क था कि लड़की वेस्टर्न टॉप, जींस जैसे पहनकर कपड़े पहनती है, जिससे मोले-मोले लड़की पर गलत असर पड़ता है। अगर कोई लड़की अशालीन दिखने वाले कपड़े पहनकर खुले आवाज में चले, तो अवश्य ही समाज को आपत्ति जताने का अधिकार है। आक्षेप दिखाना अगर दूसरे लोग पर पड़ता है और हमारी संस्कृति खराब होती है।

हम मानते हैं कि महिलाओं को अपनी इच्छा से वस्त्र धारण करने का अधिकार है। फिर भी, उन्हें सामाजिक न्याय, अपनी संस्कृति और मान्यताओं को देखते हुए ही वस्त्र और अपूर्ण धारण करना चाहिए। हर समाज की एक तब मर्यादा होती है। शालीन कपड़े पहनने से समाज में अनुशासन और अच्छी परंपरा बनी रहती है। वकीलों को संस्कृति और मान्यता प्रतीक माना जाता है। सार्वजनिक पहनावा संस्कृति को आमो बढता है। कपड़े पहनने से अनावश्यक ध्यान आकर्षित नहीं होता, इससे महिलाओं की सुरक्षा पुख्ता होती है। भड़काने दिखने वाले कपड़े पहनने का चलन परिश्रम का है, जहाँ हमारा देश नैसी सभ्यता संस्कृति और मर्यादा का अभय

महिलाओं को मोहरा बनती राजनीति



तुलसी गजमकार | प्रोफेसर, एसजीआईएफआर

मौजूबत राजनीति में, जब विरोधी असल मुठों पर जीत नहीं पाते, तो वे एक-दूसरे और विपक्षी चाल का सहारा लेते हैं। वे 'विरोधी' को नजदकी महिलाओं को मोहर के तहत इस्तेमाल करने लगते हैं। यह तरीका विपक्षी जितनी ही पुरानी सच पर टिका है कि सार्वजनिक जीवन में महिला को बहुत हद तक हतोत्साहित कर दिया, बल्कि एक ऐसी कमनीय है, जिसका इस्तेमाल पुरुष के खिलाफ किया जा सकता है।

सार्वजनिक जीवन में सक्रिय महिलाओं को 'प्रॉक्सि टारगेट' किया जाता है। किसी अन्य के लिए उन्हें निशाने पर ले लिया जाता है। राजनीति में सक्रिय लोग सस्ती बयानबाजी करके अपना फायदा तो उठा लेते हैं, लेकिन लक्षित महिलाओं से उनकी नीय, सम्मान और मेहनत से अर्जित पहचान छीन लेते हैं। यह खुले आम लैंगिक भेदभाव है आगे बढ़कर महिलाओं के प्रति छिपी हुई नफरत (मिसेजिन) और पूर्वाग्रह है। फिलम अभिनेता विजय के औपचारिक रूप से राजनीति में उतरने और अपनी पत्नी शुरू करने के बाद तमिलनाडु की सिनियर सेमि हुई महिला पत्रकारिता पर गौर करें। उनकी राजनीतिक सोच पर बात करने के बजाय, आलोचक उनके खिलाफ जल्द ही व्यक्तिगत आक्षेप लगाते हैं और चरित्र-हत्या पर उतार हो गए, जिसमें खासतौर से गुला कृष्णन का जिक्र किया गया। तमाम वक्तों, सीनेल मीडिया मंचों और सार्वजनिक रैलियों में, विरोधियों ने विजय को राजनीतिक पंथरता को कमतर दिखाने के लिए बार-बार गुला का नाम लिया। इस जहरीले माहौल में, कृष्णन को, जिनका दो टपका का फ्लेमो करियर है और जो अपने दम पर आगे बढ़ने वाली कलाकार हैं, एक पेशेवर के तौर पर देखने के बजाय एक सिनारी मोहरा बना दिया गया। उनकी मौजूदगी को ऐसे पन बना दिया गया, जैसे वह विजय को अविश्वसनीयता या नैतिक पतन की निशानी है।

इन सबसे वोटों को बेवकूफ बनाने की संदेश मिला कि कोई पुरुष नेतृत्व के लिए कितना उपयोगी है, उसको

तृषा कृष्णन और जॉर्जिया मेलोनी के साथ आभासी दुनिया में जैसा बर्ताव हुआ, उससे यह फिर पुष्ट हुआ कि मर्दों को कमजोर दिखाने के लिए स्त्रियों का इस्तेमाल किया जाता है।



इसी बात से माया जाता है कि महिलाओं के साथ उसके संबंधों को कितना सनसनीखेज बनाया जा सकता है। ऐसा करके हनु महिला को उसकी अपनी उपस्थितियों से अलग कर दिया जाता है और उसे एक राजनीतिक बोल समझा जाता है।

यह प्रवृत्ति सिर्फ क्षेत्रीय राजनीति में नहीं है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय कूटनीति तक फैली हुई है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के बारे में सोशल मीडिया के मंचों पर हो रही चर्चाओं पर गौर कीजिए। इसे दो संक्षेप राश्ट्रों के बीच राजनीतिक सहयोग और कूटनीतिक तालमेल के रूप में देखा जाना चाहिए था, लेकिन विरोधियों ने इसे 'मोदी' मीम में बदल दिया। कूटनीतिक तस्वीरों और आभासी बातचीत का बार-बार इस्तेमाल करके केंद्र सरकार का मजाक उड़ाया गया।

बेशक, कुछ लोगों ने इसे आभासी मजाक या लोगों को लक्ष्य-फुलकी चुटकी बतकर खारिज कर दिया, लेकिन करीब से देखने पर यह पटन एक अलग ही कहानी बयां करता है। इटली की पहली महिला

प्रधानमंत्री होने के नाते मेलोनी को शक्तिशाली और दूरबीय संघ की जटिल राजनीति और वैश्विक भू-राजनीति के संदर्भ में समझना चाहिए, लेकिन आलोचकों ने उनकी कूटनीति को इंटरनेट पर प्रचलित रूढ़ियों और सस्ती टिप्पणियों तक सीमित रखा, जिसमें उनके नीतिगत कदमों या विदेश संबंधों पर उनके रख का कोई जिक्र नहीं किया गया।

गुला कृष्णन और जॉर्जिया मेलोनी के साथ आभासी दुनिया में जैसा बर्ताव हुआ है, उन्मै एक बात समझने के लिए पुरे को कमजोर दिखाने के लिए महिलाओं का इस्तेमाल किया जाता है। दोनों ही मामलों में राजनीतिक निशाने पर पुरुष नेता थे, पर खामियाबाज उनकी नजदीकी महिला को भुगतना पड़ा, जिसकी सार्वजनिक छवि है। इससे राजनीति में मौजूद दोहरे मापदंडों को सचवाई बेपरदा होती है। पुरुष नेताओं को उनकी सत्ता, उनके भाषणों, उनकी आर्थिक नीतियों और कामकाज के आधार पर आंका जाता है, पर जब विरोधी उन्हें हतोत्साहित या बंदनाम करना चाहते हैं, तो वे जेंडर-आधारित नैतिकता व नीति संबंधों का सहारा लेते हैं।

मनसा वाचा कर्मणा अछे चरित्र का आधार

आज संसार में चरित्र का संकेत सबसे विकट होता जा रहा है। पुरुषों पर भारत एक ऐसा राष्ट्र है, जहाँ चरित्र निर्माण पर विशेष जोर रहा है। फिर भी आज अनेक प्रश्न हैं, जो खड़े हो रहे हैं। तमाम लोग जानते हैं कि अहिंसा का क्या महत्व है, फिर भी हिंसक हैं और सत्य का क्या महत्व है, फिर भी असत्य बोलते हैं। लोगों अपने ज्ञान को परिपक्व नहीं बनाते हैं। ज्ञान को चरित्र में नहीं उतारते हैं। कहा जाता है, धन नष्ट हुआ, तो कुछ नष्ट हुआ, शास्त्र नष्ट हुआ, तो कुछ नष्ट हुआ और यदि चरित्र नष्ट हुआ, तो सब कुछ नष्ट हुआ। भारत एक चरित्र प्रधान देश रहा है। यहाँ के संतों, गुरुओं, आचार्यों ने संपूर्ण संसार को ज्ञान का पाठ ही नहीं पढ़ाया, ज्ञान का परिपक्व स्वरूप भी संसार को दिया। इसके साथ ही अपने चरित्र में भी ज्ञान को उतारा। पुरी पुण्डित को चरित्र की शिक्षा देने वाला देश भारत ही है।

भारत में बड़ी संख्या में परिवर्तित महिलाओं का अस्तित्व एक बहुत बड़ा पत्थर है, एक उन्नत अवस्था है। यदि कोई स्त्री अपने पति को ही सब कुछ समझती है, उन्हीं के लिए आदर रखती है और सेवा में समर्पित रहती है, तो उसे पतिव्रता बोलते हैं। पति के लिए विरसक सभी बातें हो, वह पतिव्रता। पति की सभ्यता, उन्हीं के लिए विरसक, पति से अनुकूलता, इसे के लिए उन्हीं के पतिव्रता कहा जाता है। यह ज्ञान के जीवन का साधारण उन्मै उन्नत चरित्र में है। यह समाज का आधार है। चरित्रवान स्त्रियों ही श्रेष्ठ समाज की रचना करती हैं।

शायी को जो प्रथा है, वह बहुत उपयोगी है। यदि विवाह नहीं होता, तो सम्बंधों का बड़ा प्रभुत्व स्पष्ट बन जाता। पत्नी यदि पति के लिए समर्पित हो, तो परंपरा टूट जाती है। परिवार टूटता है, तो समाज टूटता है। और-

यह स्थिति तब और गंभीर हो जाती है, जब महिला आकर्षक होती है। कृष्णन और मेलोनी इंग्लैंड में चुने गए उदाहरण नहीं हैं। खूबसूरत होना ही उन्हें लोगों का ध्यान खींचने से बचाने बनाती है। ऐसी आकर्षक महिलाएं दो वक्तों से राजनीति के लिए मुखर हो जाती हैं- पहली, उनके हाथ-पांव चूँकि असली होते हैं, और दूसरी, आरोग्य को बल देने में आसानी होती है, और दूसरी, आलोचकों के लिए असल मुठों के बजाय तमाशा पर उतार आसान हो जाता है। जिस खूबी के कारण उनको सार्वजनिक जीवन में कामयाबी मिलती है, उसी खूबी का इस्तेमाल उनके खिलाफ किया जाता है।

इसी आदर से सार्वजनिक जीवन को बहुत नुकसान पहुंचता है। पहला, इससे राजनीतिक चरित्र का स्तर गिरता है और गंभीर वैचारिक विमर्श के बजाय चर्चा खिनी आरोग्य पर टकरा जाती है। दूसरा, यह एक खतरनाक माहौल बनाती है, जिसमें महिलाएं उन पेशों में आने, काम करने या बोलने से कतराने लगती हैं, जिसमें ज्यादा दिखने या सुर्खियों में रहने का अवसर हो। जयपुर प्रसिद्धिदाता में महिलाओं को सिक्कर बनाया जाने लगता है, तो हर महत्वाकांक्षी महिला को वही समझ में आता है कि किसी और के राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत से तैयार पर उतरी हो ज्यादा काम की बात नहीं है।

इस आदर से सार्वजनिक जीवन को बहुत नुकसान पहुंचता है। पहला, इससे राजनीतिक चरित्र का स्तर गिरता है और गंभीर वैचारिक विमर्श के बजाय चर्चा खिनी आरोग्य पर टकरा जाती है। दूसरा, यह एक खतरनाक माहौल बनाती है, जिसमें महिलाएं उन पेशों में आने, काम करने या बोलने से कतराने लगती हैं, जिसमें ज्यादा दिखने या सुर्खियों में रहने का अवसर हो। जयपुर प्रसिद्धिदाता में महिलाओं को सिक्कर बनाया जाने लगता है, तो हर महत्वाकांक्षी महिला को वही समझ में आता है कि किसी और के राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत से तैयार पर उतरी हो ज्यादा काम की बात नहीं है।

यदि समाज इस राजनीतिक प्रवृत्ति को बदल सकता है, तो वह एक ऐसे संस्कृति को बसावा देता है, जो महिलाओं के सम्मान और स्वायत्तता को सार्वत मानते है। बलिहाज, इस पर चर्चा करने को खास जरूरत है, क्योंकि यह राजनीति प्रवृद्धिदाता में महिलाओं को केवल के रूप में इस्तेमाल करके उनको चर्चा या दिखने को एक कपाट बेपरदा करती है। पुरुष नेताओं को उनकी सत्ता, उनके भाषणों, उनकी आर्थिक नीतियों और कामकाज के आधार पर आंका जाता है, पर जब विरोधी उन्हें हतोत्साहित या बंदनाम करना चाहते हैं, तो वे जेंडर-आधारित नैतिकता व नीति संबंधों का सहारा लेते हैं।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)



हर्ष पी पंत | प्रोफेसर, किंग्स कॉलेज लंदन

सीधो चुनौती नहीं है। तालिबान अब इस्लामवाद की परंद को न केवल दुनिया रहा है, बल्कि चुनौती भी दे रहा है। इसके उदाहरण, भारत में अलग-अलग स्थिति अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में संस्कृत समाज है। इसकी नीति धर्म और सामाजिक व्यवस्था से आगे न्यायवादी और व्यावहारिक दृष्टिकोण पर आधारित होती हुई है। उच्चतरस्तरिय संस्कृत, मंत्रियों के दौरे, कानून में भारत की कूटनीतिक मौजूदगी, व्यापार, दवा उद्योग,

कृषि, संस्कृत और मानवीय सहायता पर वातावरण का विस्तार- ये सभी बातें तालिबान हैं कि नई दिल्ली नई राजनीतिक समझदारी के साथ जुड़ने में सक्षम दिखती है। इसका मतलब यह नहीं है कि तालिबान का समर्थन कर रहा है। बल्कि, यह इस बात को समझने का तरीका है कि राजनीतिक रूप से स्त्री बरकरार काबुल पर अपना प्रभाव नहीं कायम किया जा सकता। जैसे-जैसे पाकिस्तान और तालिबान के रिश्ते बिगड़ रहे हैं, भारत का महत्व बढ़ रहा है।

नई दिल्ली के लिए इस जुड़ाव का मतलब है, अफगानिस्तान में अपनी विकास परियोजनाओं और राजनीतिक हितों को बनाए रखना, इस्लामाबाद के एकाधिकार को रोकना और आतंकवाद, संस्कृत व क्षेत्रीय व्यापार जैसे मुद्दों पर वास्तविक के रिश्ते खुलना। तालिबान के लिए, भारत के साथ करीबी रिश्ते न केवल आर्थिक अवसर देते हैं, बल्कि पाकिस्तान के मुकाबले कूटनीतिक बल भी दिलाते हैं।

तालिबान समाज के बीच सत्तावाद, अफगानिस्तान न तो 1990 के दशक के बाद मजबूत माफ़ूक हो गई है और न ही उससे पहले वाला गणराज्य (यह जयपुर प्रसिद्धिदाता, लेकिन दमनकारी देश है, जो आर्थिक रूप से सीमित होने के बावजूद अपने पड़ोसीयों से जीने से खुश रहा। भारत के लिए चुनौती नहीं है कि वह तालिबान को सत्ता वास्तविक तो करे, लेकिन उसके 'हिस्टर' को सामान्य न माने।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)



अहिंसी वैष्णव | लेखक

जब हम तेज गति से देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो इसकी सबसे बड़ी ताकत और साधक हमारे देश के युवा हैं। शिक्षा, कौशल, स्टार्टअप, नवाचार, खेल और नई तकनीकों से वे नए भारत की दिशा तय कर रहे हैं।

मन मुताबिक पहनने का हो अधिकार

दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति का यह फैसला कि हरेक व्यक्ति को अपनी परंद के कपड़े पहनने का अधिकार है, बिल्कुल उचित है और इसे लोकतांत्रिक समाज के अनुकूल ही कहा जाएगा। अदालत का यह फैसला भी जाबजबा कि सभी को दूसरी की सीमाओं का आदर और सम्मान करना चाहिए। हमें उच्च न्यायालय की इस दिशानिर्देश को सम्मान के साथ स्वीकार करना चाहिए। वैसे भी, टॉप और जींस जैसे कपड़े पहनने की आदत ही हमारे समाज का हिस्सा है।

कपड़ों को परंद और शालीनता का निष्पक्ष व्यक्तिगत स्वतंत्रता, संस्कृतिक मूल्यों और सामाजिक दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है। आधुनिक कानूनों और मानवाधिकारों के अनुसार, महिलाओं को अपनी परंद के कपड़े पहनने का पूरा-पूरा अधिकार है और किसी भी व्यक्ति के पहनने को उसके साथ होने वाले

दुर्घटनाओं या अपराध का कारण नहीं माना जा सकता। चाहे वह महिला टॉप, जींस पहने या अन्य कोई स्वेटर पहने, वह समाज को मालूम देना चाहिए कि वह अपने बारे में अच्छा-बुरा सोचने-समझने में पूरी तरह स्वतंत्र और स्वतंत्र है। इसलिए हर स्त्री को अपनी ही पहनावा है, जिनकी किसी पुरुष को हो सकती है।

असल में, समस्या हमारे सामाजिक परिवेश में है, जो सामाजिक और पुरुषवादी किस्म से प्रभावित है। ऐसे समाज के अंदर ऊंच-नीच में बाँटकर तन न्याय से दूरता है। यह लोगों को खान-पान, पहनावे, चलन-चलाने की अपनी दृष्टि से परिभाषित करना चाहता है। ऐसे समाज को बदलना हर लोकतांत्रिक और जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए। वह किसी उच्चरी टिप्पणियों और मानसिकता को अपने नामरसक हो जाना।

प्रियंका चौधरी, दिपण्डीकार

5:8380

5	4	1	2	7	3	9
9	6	5	3	8	4	1
1	9	7	8	2	6	5
3	5	2	9	1	8	4
4	3	6	7	5	9	2
2	1	8	4	6	7	3
7	2	9	6	3	5	8
8	7	4	5	9	1	6
6	8	3	1	4	2	7

Lifetime Free Newspapers Access

Editorials PDF

- English Editorials PDF with International Newspapers Editorials [35-40 pages]
- Hindi Editorials PDF
- Daily Vocabulary PDF

Magazine Channel

National & International
[General & Exam related]

International Newspapers

Newspapers around world.
Asian, European & American

Hindi Newspapers

- 1) दैनिक जागरण
- 2) जनसत्ता
- 3) हरिभूमि
- 4) हिंदुस्तान

Indian Newspapers Channel

1. The Indian Express

2. The Hindu

3. Business Line

4. Financial Express

5. Times of India

6. Hindustan Times

7. Economic Times

8. Live Mint

9. Business Standard

